industrial workers was 202 for January, 1991 and 225 for December, 1991 (latest available).

(d) The Government has taken a number of measures to check the inflationary pressure in the economy. These include: strict fiscal discipline through reduction in fiscal deficit and growth of money supply and bank credit against price-sensitive essential commodities, more effective management of supply and demand of essential/ sensitive commodities and strict action against hoarders and profiteers. Incentives are being provided for raising production to ensure medium-term stability in prices.

विदेशी ऋणों के लिए मानदंडों का उदार बनाया जाना

133. **श्री अजीत जोगी:**
कुमारी सुशीला तिरियाः

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या निर्यातोन्मुखी परियोजनाओं और लघु-स्तरीय औद्योगिक एककों के लिए विदेशी ऋण लेने हेतु मानदंडों को उदार बनाये जाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) और (ख) जी, नहीं। ऐसा कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। तथापि विदेशी करेंसी-ऋणों के अनुमोदन के लिए राष्ट्रीय प्राथमिकताओं, भुगतान शेष की अदायगी—स्थिति और अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजारों में हुई गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर मानदण्डों की समीक्षा की जाती है।

जीवन बीमा निगम द्वारा मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा को वित्तीय सहायता दिया जाना

134. **श्री अजीत जोगी:**
कुमारी सुशीला तिरियाः

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान जीवन बीमा निगम द्वारा मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा राज्यों को विभिन्न योजनाओं के अधीन कितनी-कितनी वित्तीय सहायता दी गई; और

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए जीवन बीमा निगम द्वारा जिन योजनाओं पर विचार किया जा रहा है उनका ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि निर्धारित की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान उड़ीसा और मध्य प्रदेश के राज्यों में जीवन बीमा निगम द्वारा किया गया निवेशः

(करोड़ रुपए)

योजना	उड़ीसा		मध्य प्रदेश	
	1989-90	1990-91	1989-90	1990-91
1. राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	22.75	28.00	10.77	17.00
2. भूमि विकास बैंक ऋणपत्र	—	—	3.00	—
3. राज्य बिजली बोर्ड बांड	—	—	—	10.00
4. राज्य वित्तीय/औद्योगिक विकास/औद्योगिक निवेश निगम	—	1.00	1.50	2.00
5. म्यूनिसिपल एवं पत्तन न्यास ऋणपत्र	—	—	—	—
6. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	—	—	—	—
निम्नलिखित को ऋण दिए गए:				
7. सामाजिक आवास योजनाओं के लिए राज्य सरकारें	5.29	6.90	4.64	4.69
8. शीर्ष सहकारी आवास वित्त समितियां, आवास बोर्ड और अन्य प्राधिकरण	5.00	5.00	6.00	7.00
9. जल आपूर्ति योजनाओं के लिए राज्य सरकारें/नगरपालिकाएं/जिला परिषदें, आदि	1.70	1.07	1.60	6.29
10. राज्य बिजली बोर्ड	20.55	17.39	86.29	72.29